विदेशों में भारतीय जड़ी-बूटियों की मांग

1557. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय जड़ी-बूटियों की मांग बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से किन-किन देशों को कितने कितने मूल्य की जड़ी-बूटियों का निर्यात किया गया ; और

(ग) जड़ी-बूटियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इनके उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य और खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जड़ी बूटियों के पौधों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :

	(करोड़ रुपयों में)
1982–83	21.36
1983–84	43.87
1984–85	79.17

जिन प्रमुख देशों को इनका निर्यात किया गया है वे हैं––संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, स्पेन, सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया, जापान, सिंगापुर आदि ।

[स्रोत : मूल रसायन, भेषज, सौन्दर्य-प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई]

(ग) सरकार पौध जाति की दुलर्भ औषधियों के उत्पादन, संग्रहण, तथा संरक्षण करने के उद्देश्य से जड़ी बूटियों के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है :

(1) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने सड़कों के किनारे तथा बागों आदि में आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी प्रणालियों में आमतौर पर प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियों के पौधों को उगाने के लिए कार्यवाही करने का अनुरोध करते हुए राज्य सरकारों को लिखा है ।

(2) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों, भारत सरकार से संबंधित विभागों तथा भारतीय चिकित्सा प्रणाली के व्यापारियों तथा विनिर्माताओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली औषधियों संबंधी केन्द्रीय प्रकोष्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(3) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय चिकित्सा प्रणाली में बड़े पैमाने पर प्रयोग होने वाली जड़ी बूटियों के पौधों की खेती, संग्रहण, पुनसृर्जन आदि के विभिन्न पहलुओं पर चार क्षेत्रीय सेमिनार भी चला रहा है जिनके बाद एक राष्ट्रीय सेमिनार होगी ।

Supply of foodgrains on subsidized rates to Economically weaker sections

1558. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government have recently made arrangements for the supply of foodgrains to economically weaker sections at subsidized rates; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI AJIT PANJA): (a) and (b) Yes, Sir. The Government has recently introduced the scheme for supply of foodgrains at specially subsidised prices to the people living in the Integrated Tribal Development Project areas and the tribal majority States. Under the scheme, wheat is distributed at Rs. 1.50 per kg. and common rice at Rs. 1.85 per kg.